न्यूज डायरी

उत्तर कोरिया में अपने लेदर कोट की नकल से भड़का तानाशाह

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) प्योंगयांग। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन देश में अपने लेदर कोट की नकल किए जाने पर भड़क गया है। इसके बाद में उत्तर कोरिया ने किम जोंग उन के इस पसंदीदा लेदर कोट की नकल पहनने पर बैन लगा दिया है। किम जोंग उन ने साल 2019 में पहली बार इस लेदर कोट को पहना था। इसके बाद उत्तर कोरिया के उच्च वर्ग के लोगों ने तानाशाह के प्रति अपनी निष्ठा को प्रदर्शित करने के लिए इस कोट से नकल को पहनना शुरू कर दिया। उत्तर कोरिया ने हाल ही में फैशन पुलिस को उन दुकानों को बंद करने के लिए तैनात कर दिया जिसमें इस तरह की लेदर कोट बिक रही थी। यही नहीं इस कोट को पहनने से भी लोगों को रोका जा रहा है। उन्हें यह डर सता रहा है कि सभी लोगों के इस तरह की कोट को पहनने से किम जोंग उन की सत्ता की हनक कम हो जाएगी।

परमाणु बम बनाने में पाकिस्तान की मदद कर रहा चीन, अमेरिका ने लगाया बैन

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) इस्लामाबाद। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन हमारे धुर विरोधी पाकिस्तान को परमाणु बम और मिसाइलें बनाने में मदद कर रहा है। चीन और पाकिस्तान की इस नापाक साशिज का खुलासा होने के बाद अमेरिका ने ड्रैगन की दर्जनों कंपनियों को व्यापार की काली सूची में डाल दिया है। अमेरिका ने इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया है। यही नहीं प्रतिबंधित कंपनियां चीन की सेना पीएलए को क्वांटम कंप्यूटिंग के प्रयासों में भी मदद कर रही थीं। यही नहीं अमेरिका ने चीन और पाकिस्तान के 16 संगठनों और लोगों को काली सूची में डाल दिया है। इन पर पाकिस्तान के परमाणु गतिविधियों या मिसाइल कार्यक्रम में योगदान का आरोप है। चीन, जापान, पाकिस्तान और सिंगापुर के कुल 27 नए संगठनों को काली सूची में डाला गया है। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री गिना रैमोंडो ने अपने एक बयान में कहा कि इस कदम से अमेरिकी तकनीक की मदद से पाकिस्तान के असुरक्षित परमाणु कार्यक्रम या मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगेगी।

यूएई के इंस्पेक्टर जनरल अल–रईसी बने इंटरपोल के अध्यक्ष

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) इस्तांबुल। वैश्विक पुलिस एजेंसी इंटरपोल के निर्वाचित इंस्पेक्टर जनरल अहमद नासेर अल–रईसी को गुरुवार को अध्यक्ष चुना गया है। गौर करने वाली बात यह है कि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के इस अफसर पर दक्षिणपंथी संगठनों की ओर से कई आरोप लगाए जाने के बावजूद यह निर्णय लिया गया। जनरल नासेर पर बंदियों को प्रताड़ित करने का आरोप है। मेजर जनरल अहमद नासेर अल–रईसी यूएई के गृह मंत्रालय के इंस्पेक्टर जनरल हैं। अहमद नासेर अल–रईसी का निर्वाचन चार साल के एक कार्यकाल के लिए हुआ था लेकिन मानवाधिकार संगठनों ने उन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने यूएई में बंदियों को शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी थीं। साथ ही उन पर रिश्वत लेने के अलावा भी कई अन्य अपराधों के आरोप लगे हैं।

राष्ट्रपति बाइडन की आंत से निकाली गांठ, भविष्य में बन सकता था कैंसर

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की बड़ी आंत से पिछले हफ्ते एक गांठ निकाली गई है, जिसमें कैंसर होने की आशंका थी। उनके पेट में धीरे–धीरे बढ़ रहे इस ट्यूमर (कोलोन पोली) में भविष्य में कैंसर होने के लक्षण थे। अमेरिकी राष्ट्रपति का इलाज कर रहे चिकित्सकों ने यह जानकारी दी है। गांठ यानी ट्यूबलर एडोनोमा के नमूने को जांच के लिए भेजा गया था। यह वैसी ही गांठ थी जैसी बाइडन को वर्ष 2008 में भी हुई थी और आपरेशन करके हटा दी गई थी। राष्ट्रपति के चिकित्सक डा.केविन सी ओकोनोर ने व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक मेमो में बताया कि भविष्य में इस बीमारी की निरंतर निगरानी की आवश्यकता बताई गई है। पिछले ही हफ्ते बाइडन 79 वर्ष के हुए हैं जो अमेरिका के अब तक के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति भी हैं।

इमरान के राज में कर्ज और देनदारी हुई सबसे ज्यादा

तबाही

पाकिस्तान का कुल कर्ज और देनदारी 50.5 ट्रिल्यन रुपये के आंकड़े को पार

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

इस्लामाबाद। पाकिस्तानी जनता को विकास के बड़े–बड़े सपने दिखाकर सत्ता में आने वाले प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश की अर्थव्यवस्था को तबाही की कगार पर ला दिया है। हालत यह हो गई है कि पहली बार पाकिस्तान का कुल कर्ज और देनदारी 50.5 ट्रिल्यन रुपये के आंकड़े को पार कर गई है। ताजा आधिकारिक में खुलासा हुआ है कि केवल इमरान सरकार के काल में 20.7 ट्रिल्यन रुपये का इजाफा हुआ है।

पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सितंबर 2021 तक के कर्ज के आंकड़े जारी किए हैं। वह भी तब जब एक दिन पहले ही इमरान ने माना था कि बढ़ता हुआ कर्ज राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन गया है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कुल कर्ज और सार्वजनिक कर्ज की स्थिति वर्तमान इमरान खान सरकार में लगातार खराब होती जा रही है। इमरान के काल में पाकिस्तान के कर्ज में 70 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है।

प्रत्येक नागरिक पर 91 हजार रुपये का कर्ज बढ़ा: जून 2018 को प्रत्येक पाकिस्तानी के ऊपर 144,000 रुपये का कर्ज था जो अब सितंबर में बढ़कर 235,000 हो गया है। इस तरह से इमरान के काल में देश के प्रत्येक नागरिक पर 91 हजार रुपये का कर्ज बढ़ा है जो करीब 63 फीसदी है। पिछली सरकारों की तरह से ही इमरान खान सरकार विदेशी और घरेलू कर्जों के नीचे दबती जा रही है। वहीं इमरान सरकार आय बढ़ाने में फेल रही है जिससे कर्ज के बोझ को घटाया नहीं जा सका है। इमरान के राज में सार्वजनिक कर्ज में 16.5 ट्रिल्यन रुपये की वृद्धि हुई है। पाकिस्तान की पीटीआई सरकार ने हर दिन सार्वजनिक कर्ज में 14 अरब रुपये की वृद्धि हुई है। यह नवाज शरीफ के कार्यकाल के समय से दोगुने से भी ज्यादा है। कर्ज के पहाड़ तले दब रहे पाकिस्तान को बचाने में इमरान बुरी तरह से फेल साबित हुए हैं। इमरान ने खुद माना है कि पाकिस्तान पाई–पाई को तरस रहा है।

हमारे पास पैसा नहीं है जिससे देश को चलाया जा सके: इमरान खान ने अपने हालिया बयान में मान लिया है कि उनका देश कंगाल हो गया है। इमरान ने कहा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे पास पैसा नहीं है जिससे देश को चलाया जा सके। इसी वजह से पाकिस्तान को कर्जा लेना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जिस घर में खर्च ज्यादा हो और आमदनी कम हो तो वह घर हमेशा दिक्कतों से घिरा रहेगा, कुछ यही हाल पाकिस्तान का हो गया है। इमरान खान ने कहा कि खर्च ज्यादा होने की वजह से पाकिस्तान निवेश नहीं कर पा रहा है और इससे देश का विकास नहीं हो पा रहा है। दरअसल, लोन लेकर लोन चुका रहे कंगाल पाकिस्थतान को अब विदेशी एजेंसियों से कर्ज नहीं मिल पा रहा है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को एक अरब डॉलर का लोन देने से इनकार कर दिया है।

अब आइएएमएफ से इमरान खान को मिला करारा झटका

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) इस्लामाबाद। आर्थिक बदहाली की मार झेल रहे पाकिस्थतान को अब आइएएमएफ से करारा झटका मिला है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने केंद्रीय बैंक से उधार लेने के लिए पाकिस्तान के अनुरोध को खारिज कर दिया है। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के हवाले से समाचार एजेंसी एएनआइ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि वाशिंगटन स्थित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान एसबीपी की किसी भी सार्थक जवाबदेही पर सहमत नहीं था। रिपोर्ट में कहा है कि केंद्रीय बैंक का लाभ भी इमरान सरकार को 100 फीसद हस्तांतरित नहीं किया जाएगा जब तक कि एसबीपी को अपनी मौद्रिक देनदारियों को वापस करने के लिए कवर नहीं मिल जाता।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों के मुताबिक स्टेट बैंक के लाभ का कम से कम 20 फीसद अब केंद्रीय बैंक के खजाने में तब तक रहेगा जब तक कि उसको पाकिस्तान की सरकार से मनचाहा कवर नहीं मिल जाता है। आईएमएफ कार्यक्रम के तहत सितंबर 2022 तक स्टेट बैंक से सरकारी उधारी पर प्रतिबंध है। एक मसौदे में कहा गया है कि बैंक सरकार या किसी सरकारी स्वामित्व वाली संस्था या किसी अन्य सार्वजनिक संस्था को कोई प्रत्यक्ष कर्ज या गारंटी नहीं देगा।

आर्कटिक समुद्र में लगा लंबा जाम, 11 इंच मोटी बर्फ में फंसे 24 जहाज

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) मास्को। आर्कटिक समुद्र के जरिए यूरोप और एशिया तक पहुंचने का सपना देखने वाले रूस को करारा झटका लगा है। रूसी मीडिया में आई खबरों के मुताबिक रूस के तट के पास आर्कटिक समुद्र में अनुमान से पहले बर्फ के जम जाने के कारण कम से कम 24 जहाज समुद्री बर्फ में फंस गए हैं। बर्फ जमने के कारण यह पूरा नार्दन सी रूट बंद हो गया है। इन जहाजों को निकालने के लिए अब रूस को बर्फ को काटने वाले जहाजों को भेजना पड़ा है। रूस ने इस नार्दन सी रूट के रास्ते को खोलने के लिए काफी पैसा खर्च किया है लेकिन अब उसका बर्फ जमने का अनुमान फेल हो गया है। रूसी अधिकारियों ने पहले घोषणा की थी कि यह रास्ता पूरे नवंबर महीने तक खुला रहेगा।

स्वीडन की पहली महिला पीएम ने नियुक्ति के कुछ घंटे बाद ही दिया इस्तीफा

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

स्टॉकहोम। स्वीडन की सोशल डेमोक्रेट नेता मैग्डेलेना एंडरसन को संसद द्वारा स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था, लेकिन उन्हें चयन के तुरंत बाद इस्तीफा देना पड़ा। दरअसल ग्रीन पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसके कारण उन्हें यह कदम उठाना पड़ा।

रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री चुने जाने के कुछ ही घंटों बाद, संसद (रिक्सडैग) ने विपक्ष के बजट प्रस्ताव को पारित कर दिया, जिससे एंडरसन के गठबंधन सहयोगी ग्रीन पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके

बाद एंडरसन को अपने इस्तीफे की घोषणा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रधानमंत्री चुने जाने के लिए, उन्हें 349 सीटों वाले

ग्रीन पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया

रिक्सडैग में उन्हें अधिकांश सांसदों की आवश्यकता थी।

एंडरसन को 117 का समर्थन प्राप्त था, लेकिन 174 उनके विरोधी थे, जिसमें 57 प्रतिनिधि अनुपस्थित थे। एक डिप्टी अनुपस्थित था। एंडरसन का चुनाव वामपंथी पार्टी के साथ 11 घंटे के समझौते के बाद हुआ था, जिसने सबसे गरीब 7,00,000 पेंशनभोगियों के लिए पेंशन में वृद्धि की मांग की। एंडरसन ने कहा कि वह विपक्ष के बजट के साथ देश का नेतृत्व कर सकती हैं, इसे केवल मामूली बदलावों की आवश्यकता है। हालांकि, ग्रीन पार्टी की राय अलग थी।

अफगानिस्तान में चिकित्सा आपूर्ति की भारी कमी

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) काबुल। अफगानिस्तान सरकार की स्वास्थ्य प्रणाली लंबे समय से गंभीर संकट से जूझ रही है। पिछले दो दशकों से अफगानिस्तान लगभग पूरी तरह से विदेशी सहायता पर निर्भर है। तालिबान के कब्जे के बाद में विदेश मदद लगभग रुक गई है। अफगान बच्चे गंभीर कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। देश की चिकित्सा आपूर्ति अब खत्म हो गई है। अमेरिका ने अफगानिस्तान को दी जाने वाली 9.5 बिलियन अमरीकी डालर की सहायता भी रोक दी है। एसा ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) और विश्व बैंक ने भी किया था। काबुल के इंदिरा गांधी चिल्ड्रेन हास्पिटल के तीन वार्ड बेहद बीमार और जरूरतमंदों से भरे हए है। कमरे की कमी की वजह से एक बिस्तर पर दो से अधिक बच्चों का इलाज किया जा रहा है। बाल रोग के एसोसिएट प्रोफेसर डा नूरुलहक यूसुफजई ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि अस्पताल में दवा की भारी कमी है। लोगों को भोजन तक नहीं मिल पा रहा है।